शासन 4.0: आवश्यकता और महत्त्व

यह एडिटोरियल 20/01/2022 को 'लाइवमिंट' में प्रकाशित "Envisioning Governance 4.0 For a World that must not Fail its Kids" लेख पर आधारित है। इसमें शासन के स्वरूप में क्रमिक विकास के संबंध में चर्चा की गई है।

संदर्भ

आने वाले वर्ष में कोविड महामारी और इससे पैदा हुए असंख्य संकटों में कमी आनी शुरू हो सकती है, लेकिन जलवायु कार्रवाई की विफलता से लेकर सामाजिक एकता के क्षरण तक कई ऐसी ऐसी चुनौतियाँ मौजूद हैं जिनका कोई समाधान होता नज़र नहीं आता।

इन चुनौतियों से निपटने के लिये नेतृत्वकर्त्ताओं को एक अलग और अधिक समावेशी शासन स्वरूप अपनाने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, हाल के समय में लोगों का अपने नेतृत्वकर्त्ताओं पर से भी भरोसा कम होता दिख रहा है।

सुशासन का स्वरूप या मॉडल (Good Governance Model) अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को एक अदृश्य समर्थन प्रदान करता है। यह उपयुक्त समय है कि विश्व शासन के अपने पिछले, अनुपयुक्त स्वरूपों से अब शासन 4.0 (Governance 4.0) की ओर आगे बढ़े जिसका प्रस्ताव **विश्व आर्थिक मंच** (World Economic Forum- WEF) के **दावोस शिखर सम्मेलन** में किया गया है और जो अधिकाधिक समावेशन के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक धारणा पर केंद्रित है।

शासन और इसके स्वरूप:

- **परिचय:** 'शासन' (Governance) का आशय निर्णय लेने और निर्णय लागू किये जाने की प्रक्रिया से है। इसका उपयोग कॉर्पोरेट शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन या स्थानीय शासन जैसे विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है।
- **शासन के स्वरूप:**
  - **शासन 1.0 (Governance 1.0):** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शासन 1.0 की अवधि में सार्वजनिक और कॉर्पोरेट शासन दोनों को ही एक 'मज़बूत नेता' के शासन द्वारा चिह्नित किया गया।
    - इस प्रकार का नेतृत्व एक ऐसे समाज के लिये बेहतर था, जहाँ सूचना की लागत अधिक थी, पदानुक्रमित प्रबंधन अपेक्षाकृत सुचारू रूप से कार्य करता था और तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति ने लगभग सभी को लाभान्वित किया था।
  - **शासन 2.0 (Governance 2.0):** इस मॉडल का उभार 1960 के दशक के अंत में हुआ और इसने भौतिक संपदा की प्रधानता की पुष्टि की। इसका उभार 'शेयरधारक पूंजीवाद' (Shareholder Capitalism) और प्रगतिशील वैश्विक वित्तीयकरण (Progressive Global Financialization) के उदय के साथ-साथ हुआ।
    - इस मॉडल के तहत केवल शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह प्रबंधकों ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। हालाँकि वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इस मॉडल को एक झटका दिया लेकिन इसकी संकीर्ण दृष्टि आगे भी बनी रही है।
  - **शासन 3.0 (Governance 3.0):** इसके अंतर्गत 'निर्णयन प्रक्रिया' में 'संकट प्रबंधन' काफी महत्त्वपूर्ण हो गया, जहाँ नेतृत्वकर्त्ताओं का मुख्य ध्यान परिचालन संबंधी विषयों पर रहा है और वे संभावित अनपेक्षित परिणामों के प्रति एक सापेक्षिक उपेक्षा का प्रदर्शन करते हैं।
    - कोविड संकट का उभार इसी शासन 3.0 के दौरान हुआ है और इस मॉडल के 'परीक्षण-और-त्रुटि दृष्टिकोण' (Trial-And-Error Approach) से महामारी के बेतरतीब प्रबंधन एवं प्रभाव सामने आए हैं।
- **खराब शासन के परिणाम:** खराब या कमज़ोर शासन आपदा जोखिम का चालक है और यह गरीबी एवं असमानता, खराब नियोजित शहरी विकास जैसे कई अन्य जोखिम चालकों से संबद्ध है।
  - कुशासन का परिणाम प्रायः सर्वाधिक भेद्य/संवेदनशील समूह, गरीब, कमज़ोर, महिलाओं, बच्चों और पर्यावरण को भुगतना पड़ता है।
- **एक नए शासन मॉडल की आवश्यकता:**
  - **वैश्विक शासन की अनसुलझी समस्या:** संस्थाएँ और नेतृत्वकर्त्ता दोनों ही अब अपने उद्देश्य के लिये उपयुक्त नहीं हैं।
  - चूँकि चौथी औद्योगिक क्रांति (Fourth Industrial Revolution) और जलवायु परिवर्तन द्वारा वर्तमान जीवन को बाधित किया जा रहा है, ऐसे में सार्वजनिक और कॉर्पोरेट शासन में परिवर्तन की आवश्यकता है।
  - विश्व के लिये एक नया शासन मॉडल अत्यंत आवश्यक है, जो व्यापार एवं वित्त जगत को प्राथमिकता देने के बजाय समाज और प्रकृति की प्रधानता पर ध्यान केंद्रित करता हो।

शासन 4.0 में नहिति दृष्टकिोण

- **दीर्घकालकि रणनीतकि योजना का नरि्माण:** शासन 4.0 के तहत वर्तमान अल्पकालकि प्रबंधन दृष्टकिोण को दीर्घकालकि रणनीतकि दृष्टकिोण द्वारा प्रतसि्थापति करना होगा।
    - वहीं महामारी, सामाजकि-आर्थकि संकट और मानसकि स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर ध्यान देने के साथ-साथ जलवायु परविर्तन से नपिटने के लयि कार्रवाई, मानव गतविधिि से होने वाली जैव ववििधिता की हानि एवं पर्यावरण की क्षतिको दूर करने और अनैच्छकि प्रवास जैसी संबंधति चुनौतियों को संबोधति कयि जाना भी आवश्यक है।
- **व्यवसायों द्वारा उत्तरदायत्वि ग्रहण करना:** नए मॉडल के अंतर्गत अतीत के 'टनल वज़िन' (Tunnel Vision) या संकीर्ण दृष्टकिोण और अद्योमुखी दृष्टकिोण (Top-Down Approach) को प्रतसि्थापति करना होगा। वसिंगतियों से भरी जटलि और परस्पर-संबद्ध दुनयि में समाज के प्रत्येक हतिधारक की भूमकिाओं में परविर्तन लाया जाना चाहयि।
    - व्यवसाय अब अपने सामाजकि एवं पारसि्थतिकि प्रभावों की उपेक्षा नहीं कर सकते और यह जवाबदेही सरकार की होगी कि वह सुनश्चिति करे कि व्यवसाय उत्तरदायत्वि ग्रहण करें।
- **उभरती प्राथमकिताएँ:** अर्थशास्त्र की संकीर्ण अवधारणा और अल्पकालकि वत्तिीय हतिों पर बल देना बंद करना होगा। इसके बजाय समाज और प्रकृतिकी प्रधानता कसिी भी नई शासन प्रणाली के मूल में नहिति होनी चाहयि।
    - नश्चिय ही वत्ति और व्यवसाय अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं लेकनि उन्हें समाज और प्रकृतिकी सेवा करनी चाहयि, न कि समाज और प्रकृतिका उपयोग करना चाहयि।
- **नए नेतृत्वकर्त्ता:** कई नेतृत्वकर्त्ता शासन के एक नए युग का नेतृत्व करने को इच्छुक हैं, जनिमें पर्यावरण, समाज एवं शासन संबंधी मेट्रक्सि की वकालत करने वाले व्यावसायकि कार्यकारी से लेकर कुछ राजनीतकि नेता तक सभी शामलि हैं।
    - ऐसे नेतृत्वकर्त्ताओं का स्वागत कयि जाना चाहयि जो अपने संकीर्ण हतिों के बाहर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और जलवायु परविर्तन से मुकाबले तथा सामाजकि अन्याय को दूर करने के लयि वशिष्टि कार्रवाई का समर्थन करते हैं।
    - उत्तरदायी एवं अनुक्रयिाशील शासन (Responsible and Responsive Governance) का सर्वोत्कृष्ट पैमाना आज इस बात की माप करता है कि नेतृत्वकर्त्ता कसि हद तक 'अंशधारक उत्तरदायत्वि' (Shareholder Responsibility) पर 'हतिधारक उत्तरदायत्वि' (Stakeholder Responsibility) की अधभिावति को स्वीकार करते हैं और सहमति रखते हैं।
        - यद्यपि हतिधारक उत्तरदायत्वि का मापन अभी भी अपनी आरंभकि अवस्था में है, सुसंगत मेट्रक्सि का वकिास हमें यह तय करने में सक्षम करेगा कि नेतृत्वकर्त्ता अपनी भूमकिा और उत्तरदायत्वि के संबंध में एक व्यापक दृष्टकिोण अपना रहे हैं या नहीं।

अभ्यास प्रश्न: ''दुनयि बदल गई है और सार्वजनकि एवं कॉर्पोरेट शासन को भी इसके साथ बदलना होगा। महामारी के बाद का वशि्व शासन के एक नए मॉडल की अपेक्षा रखता है जो न केवल पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर वचिार करता हो बल्कि वभिन्नि सामाजकि-आर्थकि संकटों पर काबू पाने के लयि दीर्घकालकि योजना पर भी ध्यान केंद्रति करता हो।'' टप्पिणी कीजयि।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/21-01-2022/print